'राजकिशोर' की 'नैया' डुबोनो वाले, 'हरीश' के बने 'खेवनहार'!

2014 में राजकिशोर सिंह की नैया डुबोने वाले अधिकांश रणनीतिकार हरीश की टीम में शामिल होकर साथ में चल रहे

❖ इन दलबदलू रणनीतिकारों की निष्ठा और वफादारी पर हमेशा सवाल उठतें रहे ❖ यह लोग जब राजकिशोर सिंह जैसे व्यक्ति के नहीं हुए तो अन्य के क्या होंगे ❖ चुनाव के दौरान इन लोगों ने राजकिशोर के पैसे का भी खूब दुरुपयोग किया ❖ जो पैसा जहां जाना चाहिए था, वहां गया ही नहीं, और 75 फीसद पैसा रणनीतिकारों ने अपने पास रख लिया ❖ राजकिशोर के हार का कारण, सही जगह पर पैसा न पहुंचने को महत्वपूर्ण माना गया, जिसे लेकर आज भी उन्हें मलाल ❖ विपक्ष के प्रत्याशी को अगर चुनाव जीतना है, तो 2019 से आगे की सोचना होगा, मुख्य धारा के उपेक्षित दलितों को भी साथ में लेकर चलना होगा ❖ हरीश को भी विशेष वर्ग के आलावा अन्य वर्गों को भी तरजीह देनी चाहिए, इनपर लगे विशेष वर्ग के ठप्पे को मिटाना होगा ❖ पक्ष और विपक्ष के पैसे का अगर सदुपयोग हो गया, और 2014 की तरह बेईमानी और धोखेबाजी नहीं हुई तो जीतने का सपना पूरा हो सकता

तेजयुग न्यूज

बस्ती।....यह सही है, कि जिले में कोई भी ऐसा नेता नहीं हैं, जो अपने काम और छवि की बदौलत चुनाव जीत सके। होना तो यह चाहिए कि जिन्हें पांच या दस साल का मौका मिला, उन्हें जनता उनके कामों के बदौलत जीताना चाहिए। क्यों कि जीतने से पहले नेता यही कहकर वोट मांगते हैं, कि अगर आप लोगों ने जीता दिया तो वह पांच साल में विकास की गंगा बहा देगे। आप का सेवक बनकर रहेगें। वाकई, नेता अगर जनता से किए गए वादे को पूरा कर दे तो फिर उसे प्रचार-प्रसार और पानी की तरह पैसा बहाने की आवष्यकता ही नहीं पडेगी। उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी बैसागी की आवष्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग सीनाठोंक मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। उस समय इन्हें यह भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने पांच और दस साल में आप के लिए क्या-क्या किया।

जिस दिन नेता जनता के मन में यह विश्वास दिलाने में सफल रहा, कि जो वह कह रहा हैं, उसे करेगा, और पांच साल तक आपके दरवाजे पर सेवक की तरह आता रहेगा, उस दिन जनता उन्हें किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि उनके कामों पर वोट देगी, उस दिन न तो किसी रणनीतिकार की आवश्यकता पड़ेगी, और न राम, योगी और मोदी की, और न जाति की ही। राम, योगी, मोदी और जाति की आवश्यकता उन्हें पड़ती है, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। अगर, यह लोग जीतने के बाद कुछ भी न करें, सिर्फ जनता का सेवक बनकर रहें, तो इन्हें चुनाव में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सेवक शब्द सिर्फ चुनाव के दौरान ही नेतागण इस्तेमाल करते हैं, और जीतने के बाद सेवा करना तो बहुत दूर की बात हैं, सेवक ही नहीं रह जाते, चुनाव के दौरान जो नेता मतदाताओं के घर पर जाकर एक-एक वोट के लिए नाक रगड़ता है, जीतने के बाद उसी नेता से मिलने के लिए जनता को उनके आगे-पीछे घूमने वालों से सिफारिश करनी पड़ती। अगर यही एक आदर्श नेता की पहचान है, तो असली आदर्श नेता की पहचान क्या?

हम बात कर रहे थे, 2014 और आज के रणनीतिकारों की। याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह के जो रणनीतिकार रहे, वर्तमान में उनमें से अधिकांश सांसद हरीश द्विवेदी के रणनीतिकारों की टीम का हिस्सा है। जो लोग आज सांसद के टीम का हिस्सा हैं, उन्हीं में से अधिकांश लोग राजकिशोर सिंह की नैया डुबो चुके है। यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजकिशोर सिंह के लोगों का कहना है, कि आज भी भईया को इस बात का मलाल है, कि क्यों नहीं वह उन लोगों को पहचान सके, जो उनकी आस्तीन में सांप बनकर उन्हें डस रहे थे। कहते हैं, भईया की ही देन थी, जो आज यह लोग 'फारचूनर' से चल रहे है, और हैसियत वाले कहलाते है।। वरना, इन लोगों की हैसियत 'नैनो' कार से भी चलने लायक नहीं थी। कहते हैं, कि अगर यह लोग 2014 में भईया को धोखा न दिए होते और जो पैसा दिया गया था, उसका सदुपयोग करते तो भईया सांसद बनते। कहते हैं, कि भईया ने जिन लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, उन्ही में से अधिकांष लोगों ने धोखा ही नहीं दिया, करोड़ों रुपया हजम भी कर लिया। दिए गए पैसे का इन लोगों ने 75 फीसद दुरुपयोग किया, और जो 25 फीसद था, उसे भी इन लोगों ने अपने लोगों के बीच बांट दिया।

तेजयुग फॉलोअप खबर

जिन लोगों को भईया ने आबाद किया, उन लोगों ने ही भईया को बर्बाद कर दिया, और अब हरीष द्विवेदी को बर्बाद करने में लगे हुएं है। यह लोग चार भाजपा विधायकों को तो निपटा चुके हैं, और अब सांसद को निपटाने की बारी है। राजकिशोर सिंह के अनेक वफादार, सांसद को यह सुझाव दे रहे हैं, कि जो गलती भईया ने किया, उसे वह मत करें, नहीं तो पछताने और हाथ मलने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं आएगा। कहते हैं, कि यह लोग भईया की नांव डुबो चुके हैं, वही लोग सांसद के खेवनहार बने हुए है। अगर सांसद इन लोगों से सावधान नहीं हुए तो यह लोग भईया की तरह सांसद की भी नैया डुबो देंगे। कहते हैं, कि भईया के हार का मुख्य कारण, चुनाव के पैसे का दुरुपयोग होना। अगर, यही पैसा जहां के लिए दिया गया था, वहां पहुंच जाता तो कहानी कुछ और होती। हरीष को अपने उपर लगे उस धब्बे को भी धोना होगा, जो उन पर विषेष वर्ग को तरजीह देने का लगा हुआ हैं, इन्हें अन्य वर्गो को भी तरजीह देने का सुझाव दिया जा रहा है।

बहरहाल, महान वही होता है, जो इतिहास से सबक लेता है। इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता विपक्ष के प्रत्याशी को भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है, कि विपक्ष के प्रत्याशी को अगर चुनाव जीतना है, तो उन्हें 2019 से आगे की सोचना होगा, मुख्य धारा के उपेक्षित दलितों को भी साथ में लेकर चलना होगा। क्यों कि चमार वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसे में अगर किसी ने उन्हें सहारा दे दिया तो वह उसकी नैया पार लगाने में सहायक हो सकते है। इसका उदाहरण, मउ के उप चुनाव के रुप में देखा जा सकता है, जहां पर बहनजी की अपील के बाद भी चमारों ने वोट नहीं किया, जिसका परिणाम सपा प्रत्याशी का जीतना रहा। यह वर्ग और इस वर्ग के नेता भाजपा में सबसे अधिक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे है। देखा जाए तो पिछले पांच सालों में भाजपा ने इस वर्ग और इनके नेता को वह मान-सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार रहे। इनके स्थान पर चालक और रसोईया को मान-सम्मान और पद दिया, जिसे टिकट मिलने से पहले कोई जानता और पहचानता भी नहीं था। भाजपा वालों ने ऐसे लोगों को तरजीह तो दिया, लेकिन चमार कार्यकर्त्ता को नहीं दिया, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है।

'अन्नदाताओं' का 'पेट' भरे 'बिना' भारत 'शिखर' पर नहीं 'पहुंच' सकता : चंद्रेश

कृषि के क्षेत्र मे क्रांति लाना है, तो कृषि पर्यावरण प्रणाली बनानी पड़ेगी

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...अगर भारत को विकास के उच्च शिखर पर पहुंचना है, तो उसे अन्नदाताओं की आय को दोगुनी करनी होगी, और जब तक अन्नदाताओं का पेट नहीं भरेगा तब तक भारत शिर पर नहीं पहुंच सकता है। यह करना हैं, भाकियू भानु गुट के मंडल प्रवक्ता चंद्रेश प्रताप सिंह का। कहा कि अगर विकास के पथ पर चलकर भारत को विकसित किया जा सकता है तो अन्नदाताओं का विकास क्यों नहीं किया जा सकता। अगर कृषि के क्षेत्र मे क्रांति लाना है, तो कृषि पर्यावरण प्रणाली बनाना पड़ेगा। तभी किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

कहा कि कृषि विकास से भारत का विकास-किसानों के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के चैतरफा विकास के लिए नया मंत्र है। यह बात महसूस किया जा रहा है अब तक कृषि किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति दूरदर्शी सोच व कमी के कारण बड़ी संख्या मे किसान कृषि को लाभहीन मानकर खेती करना क्यों छोड़ते रहे है। क्यों हजारों किसानों ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे है। अब यह बात किताबों में ही रह गई भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश गांव किसानों से सजता है।

किसानों की दुर्दशा का कारण यह भी रहा कि उनके मेहनत व उत्पाद का अच्छा मूल्य न मिलना। कहा कि सभी दलें व सरकारें किसानों की आय दुगनी करने की किसानों के प्रति वेदना रखकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए किसान गांव नौजवान की बात करते हैं। किसानों को बुलंदियों पर ले जाने का दिव्य स्वप्न दिखाते हैं। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत। सरकार की दोहरी नीतियों व उद्योगपतियों के प्रति प्रेम मोह का परिणाम है, कि किसान दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा है। किसानों के श्रमिकों के हित में बना कानून उद्योगपतियों के लिए हितकर साबित हो रहा है। किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान 9-10 वर्षों तक तक लटका रहता है। बमुश्किल गन्ना बेचने वाला भुगतान पाता। इसी आस में वह दम तोड़ देता है, और उसके वारिस अपने उपज उत्पाद के मूल्य प्राप्ति हेतु बुड्ढे हो जाते हैं। गेहूं, धान के क्रय केंद्र लगाए जाते हैं, किसानों के हित में उसका लाभ दलाल बिचैलिए उठाते है। जिसके पास इंच और विस्से में जमीन नहीं रहती उनके नाम सैकड़ों कुंतल का धान गेहूं खरीद हो जाता है।

कहते हैं, कि किसान शिकायत पर शिकायत करता है, मगर भ्रष्टाचारियों और दलालों का कुछ भी नहीं होता। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतनी गहराई तक पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सब डुबकी लगा रहे है। हमारा देष भ्रष्टाचार ही पहचान बन चुका है। ऐसे में भला आम आदमी की कौन सुनेगा। कहते हैं, कि हमारे देश में तीन तरीके के भ्रष्टाचार से आम आवाम कराह रहा है। यह मत पूछिए कहां भ्रष्टाचार नहीं है, आखिर संस्थागत, व्यवस्थागत, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। इस युक्ति पर काम करने संघर्ष करने आंदोलन करने की आवश्यकता है। एक क्रांति की आवश्यकता है, यह तभी संभव होगा जब हम मुफ्तखोरी, हरामखोरी, फ्री का लाभ छोड़ेंगे। यह मुफ्तखोरी हरामखोरी फ्री का लाभ देश की नीव को खोखला कर दे रहा है। सरकारें चुनाव जीतने के लिए ऐसे निःशुल्क बाट रही है, जैसे मानो वह अपने जेब से दे रही है। निःशुल्क वाली सुविधा देकर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। यूरोप के कई ऐसे देष हैं, जहां पर कोई भी चीज निःशुल्कनहीं है। निःषुल्क अनाज, बिजली और पानी के चलते देश और राज्यों की आर्थिक स्थित कमजोर होती जा रही हैं। कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। फिर भी निःषुल्क वाले कल्चर से सरकारें नहीं उभर रही है।

'बिजली' विभाग से पीड़ित 'उपभोक्ताओं' को अच्छी 'खबर'

बस्ती।...छोटी मोटी समस्याओं को लेकर परेशान रहने वाले विधुत उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभाग की ओर से विधुत उपभोक्ता फोरम स्थापित किया गया। यह उपभोक्ता फोरम न्यायालय की तरह काम करेगा, और इसे पांच सदस्य होगें, जिसके मुखिया चीफ इंजीनियर होगें, उपभोक्ता की ओर से भी सदस्य नामित होगें। मुख्य अभियंता कार्यालय में उपभोक्ता फोरम न्यायालय स्थापित हुआ है। इस न्यायालय के खुल जाने से सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होगा, जो बिजली बिल को लेकर परेषान रहते हैं, और जिनका षोषण विभाग के बाबू लोग करते थे। इस फोरम के स्थापित हो जाने से सालों लंबित मामलों का निस्तारण हो सकेगा। फोरम का फैसला अंतिम होगा।

बिजली संबधित शिकायतों के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय में खुला उपभोक्ता फोरम न्यायालय

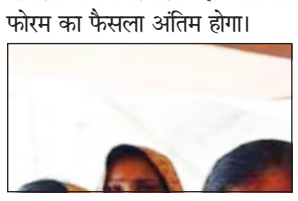

'फर्जीवाड़ा': 'होली' को भी 'कागजों' में 'मजदूरों' ने चलाया 'फावड़ा'

काम करते दिखाया 182 'मजदूर', मौके पर एक भी नहीं मिले, नकली प्रधान का कारनामा

तेजयुग न्यूज

बनकटी, बस्ती। विकास खंड बनकटी में मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का मस्टरोल निकाला जाता है, और मौके पर कहीं चार पतो कहीं पर जीरो मजदूर काम करते मिलते। फर्जीवाड़े का आलम यह है, कि होली के दिन मजदूरों से कागजों में काम करवा दिया। अब जरा अंदाजा लगाइए कि होली के दिन जो मजदूर दारु और भांग के नशे में चूर रहता, चल भी नहीं सकता, उन मजदूरों से नकली प्रधान ने काम करवा दिया।

यह वही प्रधान लोग हैं, जो कड़ाके की ठंडक रात्रि दस बजे मजदूरों की हाजीरी काम करते वक्त लगाया गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी तक को प्रधानों ने फर्जी काम करवाया। यह फर्जीवाड़ा गांव वालों और मीडिया को दिखाई देता, लेकिन बीडीओ को नहीं दिखाई देता। पड़री में छह साइड चल रहा है, जिसमें 28 को 182 मजदूर काम करते हुए दिखाया गया हैं, 22 मस्टरोल निकला हुआ है। जबकि मौके पर एक भी मजदूर काम करते नहीं मिले। इसी तरह 27 और होली वाले दिन 26 मार्च को इतनी ही संख्या में फर्जी मजदूर लगाए गए। सब फर्जी है। पडरी में पिचरोड से पोखरा खुदाई कार्य। छक्कू के खेत से जय विजय तक नाला खुदाई कार्य। पंचायत भवन के सामने भू स्थल पर विकास कार्य। पिच रोड से बाग तक नाला खुदाई कार्य। दक्षिण पोखरा खुदाई कार्य।

जिन मजदूरों को काम करते दिखाया गया उनमें राजेंद्र, सतीश चंद्र, मनीष कुमार, मंगलेश्वर, राम आशीष, फूलचंद, बीपत, अनीता देवी, नीमा, अशोक कुमार, राम सेवक, मीरा, श्रीमती, शिव शंकर, अनिल कुमार, रीता देवी, फागू राम, ध्रूव चंद, बीपत, शारदा देवी, परमिला, संगीता देवी, आरती, काली प्रसाद, शिवपूजन, रिजवानुल हक, अब्दुल वाहिद, ओंकार, सुभागी, सावित्री देवी, तिलक, सोहित, यादव, कुमारी गुड़िया यादव, गोमती, कुसुम, मीरा देवी, शारदा देवी, राम शब्द, सियाराम, सुरेश रामकेश, निर्मला, आकाश, मनोज पांडे, रघुवर, चंद्रकला, विजय शंकर पांडे, हरिश्चंद्र, शैलेंद्र हुबलाल, रामप्रीत, रामनारायण, जानकी देवी, सोना, राजेंद्र, पंचराम, विजय कुमार, माया देवी, घुरई, बुझारत, सुशीला, भोले, गंगा राम, आकाश, इंद्रा, सुशीला, नागेंद्र, इंदल, सीमा, प्रभाकर, अशोक, सच्चिदानंद, संगीता, अंगिरा, सोनी, अनिल कुमार भारती, अमित कुमार भारती, अनीता, संतोष, उमेश, मितई, उदय शंकर, अशोक कुमार, वंदना, रवि पांडे सोनी, रिंकू राव, वीर बहादुर, शनि, गोविंद, सुशीला, आकाश पांडे, बुद्धि प्रकाश, लीलावती, अध्यापक साहब, सुंदर, इंद्रेश, रामपति, महेंद्र संजय सुंदरी अखिलेश पांडे रतेश श्री राम धर्मेंद्र बुद्धू हरिराम बरसाती शीला देवी निकालो किरण सुरेंद्र कुमार राम उजागीर पप्पू संजू संजू अमृतलाल कल्पना अंगद रघुनाथ कृष्णा पूनम राम जी अमन डिंपल एवं गुड़िया अमर सिंह अभिषेक गीता देवी प्रिंस पूजा अनीता मंजू रागिनी विमल लक्ष्मी जितेंद्र शिवम आशा आरती मनोज पांडे श्रवण कुमार पांडे ध्रुव चंद्र पांडे आकाश अजीत कुमार राजमणि माया सुमन मनोज कुसुम इस्त्रावती सदन राम बाली कुमार सुग्रीव महिला अरविंद कुमार राधेश्याम पंचराम मीरा चंद्रशेखर वनवासी देवी बहु देवी आशुतोष गीता देवी सुशीला देवी शकुंतला उर्मिला रेखा रामराज महेश चंद दिलीप सुदामा अमृता देवी सीमा रामकेश गब्बर राजू राहुल कुसुम राजमती बेबी राज बहादुर जिलेब फूलमती सुखी राधेश्याम सर्वेश कमल रमाकांत।

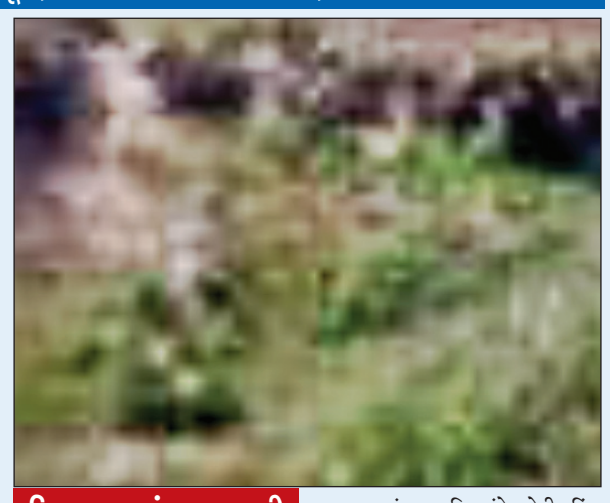

विकास खंड बनकटी के ग्राम पंचायत पड़री में छह कार्यो के लिए 22 मस्टरोल निकाला

'लेखपाल' के 'फर्जी' रिपोर्ट ने ली 'दो' की 'जान'

❖ यह पहले ऐसे 'लेखपाल' हैं, जिनकी 'कलम' पैसा मिलते ही चलने 'लगती' ❖ रिश्वत लेते समय इनका वीडियो भी वायरल हो चुका ❖ लेखपाल का नाम प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, इनकी तैनाती हर्रैया तहसील के गौर ब्लॉक के ईंटबहरा, सिधौर परागडीह सहित अन्य गांवों में ❖ फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...वह लेखपाल ही क्या, जो फर्जीवाड़ा न करता हो। लेखपाल का मतलब ही, फर्जीवाड़ा। बहुत कम ऐसे लेखपाल होगें जिनके फर्जी रिपोर्ट के चलते दो लोगों की मौत हो चुकी है। प्रेम प्रकाष श्रीवास्तव नामक इस लेखपाल साहब की कलम तब चलती है, जब इनकी जेब में लक्ष्मी आ जाती है। बिना लक्ष्मी के तो यह आंख उठाकर भी नहीं देखते, कलम चलाना तो बहुत दूर की बात। एक तो लेखपाल और उपर से लाला बिरादरी के लेखपाल। इनके बारे में बताया जाता है, कि अगर इन्हें लक्ष्मी के दर्शन हो जाए तो यह कोई भी गनत/सही काम करने को तैयार हो जाते है। इनके विवादित रिपोर्ट के चलते अनेक मुकदमें चल रहे है। हाईकोर्ट तक इनकी रिपोर्ट की चर्चा हो रही हैं। यह इतने निडर है, कि रिष्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके कलम से लोगों को न्याय कम और नाइंसाफी अधिक हुई है। इन्हें आरटीआई और आईजीआरएस में फर्जी और भ्रमित रिपोर्ट लगाने का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। इन लेखपाल साहब की तैनाती हर्रैया तहसील के गौर ब्लॉक के ईंटबहरा, सिद्धौर परागडीह सहित अन्य गांवों में है।

सिद्धौर में जमीन के बैनामा के मामले में फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ईंटबहरा के गाटा संख्या 290 का धारा 24 हुआ नहीं, और लेखपाल ने होने का रिपोर्ट लगा दिया गया, इनके खिलाफ 300 षिकायतें की गई, मगर आजतक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें हर्रैया तहसील वालों का चहेता भी माना जाता हैं। गांव वाले न जाने कितनी बार इनका हल्का बदलने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

डीएम एसपी के निर्देश मातहतों के लिए खेल

नौकरशाही के आगे बेबस नियम कानून : न्याय के लिए भटक रहे फरियादी

सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि जिला स्तरीय अधिकारियों में डीएम एसपी से फरियादियों को उम्मीदें होती हैं

तेजयुग न्यूज

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ के लाख शक्ति के बावजूद भी नौकरशाही चरम पर है कोई किसी के निर्देशों को पालन नहीं कर रहा अधिकारी भी मातहतों के आगे बेबस नजर आ रहे नतीजा फरियादी जिला मुख्यालय के अधिकारियों की चौखटों पर न्याय के लिए एड़ी रगड रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि जिला स्तरीय अधिकारियों में डीएम एसपी से फरियादियों को उम्मीदें होती हैं।

लेकिन अगर इन अधिकारियों से भी जनता को न्याय न मिले और बार बार किराया खर्च कर दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़े तो नियम कानून पर सवाल उठना लाजिमी है। एक ऐसा ही गंभीर मामला जगतपुर थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया है जहां पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस और लेखपाल की मिली भगत से कुछ दबंगों ने जबरन लाखों रुपए के पेड़ कटवा लिया जबकि पेड़

कटने की सूचना डायल 112 और लेखपाल को दी गई यही नहीं महिला डेस्क पर लिखित सिकायत दर्ज कराई गई लेकिन यह कहकर टाल दिया गया कि क्षेत्र के दरोगा नहीं है जब आएंगे तो जांच कराया जाएगा इसी दौरान गरीब परिवार के पेड़ काट लिए गए। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के नवाबगंज तहसील ऊंचाहार है।

यहां की रहने वाली माधुरी मौर्य पुत्री हरिलाल ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय लेखपाल शिवम सिंह व पुलिस की मिली भगत से विपक्षी सुनील सिंह पुत्र गिरजा दत्त सिंह तथा नरसिंह पुत्र राजबहादुर ने उनकी जमीन पर लगे लाखों रुपए के पेड़ जबरन कटवा लिए। मामले की शिकायत संबंधित थाना जगतपुर में की गई तो जगतपुर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थाने से व तहसील से न्याय न मिलने को लेकर पीड़ित परिवार ने डीएम एसपी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित माधुरी के मुताबिक उक्त भूमि में उसके हिस्से में 16 पेड़ थे जिसकी कीमत लगभग दो लाख थी। इस मामले में थाना अध्यक्ष जगतपुर बबिता पटेल का कहना है की मामला अधिक जानकारी में नहीं है देखवा लेती हूं।

महिलाएं अधिकारी फिर भी भटक रही महिलाएं

रायबरेली। जिले में अधिकतर बागडोर महिलाओं के हाथों में है बावजूद पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। सासंद से लेकर डीएम और सीडीओ से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष यही नहीं जगतपुर थाना अध्यक्ष भी महिला है फिर भी एक महिला को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर काटना पड रहा है। सवाल सिर्फ न्याय का नहीं है सवाल सिस्टम पर है।

निर्वाचन आयोग का निर्णय मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा : डीएम

तेजयुग न्यूज

बस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त जानकारी देते हुए डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि कुल 12 पहचान दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडी आईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा।

उन्होंने बताया कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पचड़ बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये है।